(d) The Government has taken the following steps to eliminate the use of DDT as pesticide:—

(i) Use of DDT has been reviewed by the Government from time to time since 1984. Consequently, its use in agriculture was withdrawn in May, 1989 and its use in public health programme is allowed upto 10,000 MT per annum.

(ii) A number of safer synthetic pesticides as well as biocides have been registered for use in public health programme. Besides, priority has been accorded for early registration of biocides.

(iii) The Central Government has cosntituted a Group in January, 1997 under the Chairmanship of Union health secretary to mandate the use of DDT in the public health programme. The use of DDT would be gradually reduced in phased manner under public health programme.

किसानों को नियंत्रण मुक्त उर्वरक बेचने हेतु धन का आबंटन

2121. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को किसानों को नियंत्रण मुक्त उर्वरक छूट पर बेचने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) किसानों को विनियंत्रित फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की बिक्री पर उर्वरक सप्लायरों को रियायत की राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त बिक्री की प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त बिक्री की प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर गत दो वर्षों के दौरान किए गए भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	(लाख रुपए)
1994-95	2641.84
1995-96	3179.57

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

तिलहनों और दालों के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

2122. **श्री राम जेठमालनी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहनों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत दालों और तिलहनों के उत्पादकों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गत वर्षों के दौरान देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1995-96 के दौरान देश में दालों और तिलहनों की उत्पादकता दर क्या रही है; और

(ङ) 2002 ई० तक इन दरों में वृद्धि करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, हां। देश में दलहन एवं तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए दो केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी) एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी) चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न जरूरी आदानों जैसे बीजों के उत्पादन एवं वितरण, मिनिकिट का वितरण, राइजोबियम कृषि, जिप्सम/पाइराइट, उन्नत फार्म उपकरण, पौध संरक्षण उपकरण, किसान प्रशिक्षण, स्प्रिंकलर सेट इत्यादि के लिए इन दो फसलों के उत्पादकों को राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी